इंदौर-देवास-उज्जैन क्षेत्र में एयरपोर्ट सिटी विकसित होगी

इंटरनेशनल एयरपोर्ट पीपीपी मोड में होगा विकसित, निवेश और व्यापार बढ़ेगा

▸ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा...

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 23 अप्रैल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वर्ष 2030 तक यात्री क्षमता 5.5 मिलियन से बढ़ाकर 10 मिलियन प्रति वर्ष तथा माल कार्गो क्षमता 20 हजार मीट्रिक टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

इसलिए प्रदेश में विमानन अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है. इंदौर-देवास-उज्जैन क्षेत्र में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ एयरपोर्ट सिटी विकसित की जाएगी. यह परियोजना पीपीपी मॉडल पर आधारित होगी, जिससे निवेश, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, जिससे प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित होंगी और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी. मध्यप्रदेश आस्था, अध्यात्म और अनुपम शिल्पकला का संगम है. उज्जैन के श्री महाकाल लोक, ओंकारेश्वर के एकात्म धाम, खजुराहो की ऐतिहासिक धरोहर और ओरछा-चित्रकूट की आस्थाएं जन-मानस में रची-बसी हैं. इन स्थलों तक सहज पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 'पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा' और 'धार्मिक पर्यटन हेली सेवा' प्रभावी माध्यम बन रही हैं. वर्तमान में यह सेवा प्रदेश के 8 प्रमुख केंद्रों—भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को आपस में जोड़कर श्रद्धा और पर्यटन को नए पंख लगा रही है.

तहसीलों तक पहुंचेगी हवाई सेवा

प्रदेश में विमानन क्षेत्र को विकेंद्रीकृत करते हुए हवाई सुविधाओं को तहसील स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. हवाई सेवाएं केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहें, बल्कि हर क्षेत्र तक पहुंचें. इसी दृष्टि से प्रत्येक तहसील ब्लॉक में हेलीपैड विकसित करने की योजना है. प्रदेश में हर 150 किलोमीटर पर एक कॉमर्शियल एयरपोर्ट, 75 किलोमीटर पर एयरस्ट्रिप और 45 किलोमीटर के दायरे में हेलीपैड विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

नागर विमानन नीति से निवेश-रोजगार को बढ़ावा

प्रदेश की सिविल एविएशन पॉलिसी-2025 विमानन क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में विमानन अधोसंरचना को मजबूत करना, निजी निवेश को आकर्षित करना और युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर सृजित करना है. नीति के तहत प्रदेश की 11 हवाई पट्टियों को उड़ान प्रशिक्षण और अन्य व्यावसायिक विमानन गतिविधियों के लिए निजी भागीदारी से विकसित किया जा रहा है. इनमें सिवनी, सागर, गुना, रतलाम, उज्जैन, बालाघाट, उमरिया, छिंदवाड़ा, मंदसौर, नीमच और शिवपुरी शामिल हैं. इससे इन क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं का विकास होगा.

क्षेत्रीय हवाई संपर्क से छोटे शहरों को मिली विकास की उड़ान

विगत दो वर्षों में मध्यप्रदेश ने हवाई सेवाओं के विस्तार में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. दतिया प्रदेश के 8वें हवाई अड्डे के रूप में अपनी सेवा दे रहा है. रीवा, सतना और दतिया की सफलता के बाद अब शिवपुरी और उज्जैन में भी नए हवाई अड्डों की तैयारी तेजी से चल रही है. रीवा हवाई अड्डा पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए विकास का नया इंजन बन चुका है. यह न केवल सीमेंट और बिजली उत्पादन केंद्रों के लिए मददगार साबित हो रहा है, बल्कि मुकुंदपुर टाइगर सफारी जैसे पर्यटन केंद्रों तक पर्यटकों की पहुंच को भी आसान बना रहा है.

एक नजर में

संगठन में प्रदेश मंत्री बने गोविंद कजरे

इंदौर. रविदास समाज के अंतरराष्ट्रीय सामाजिक संगठन श्रीगुरु रविदास विश्व महापीठ भारत के संरक्षक पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सत्यनारायण जटिया व राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर रविदासाचार्य सुरेश राठौर की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश मोहने ने गोविंद कजरे, इंदौर को संगठन में प्रदेश मंत्री पद पर नियुक्त किया है. यह नियुक्ति उनके समाजसेवा, संगठन के प्रति समर्पण और उत्कृष्ट कार्यशैली को देखते हुए की गई है. इस नियुक्ति पर श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ भारत के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश मोहने, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय रोजिया, जिलाअध्यक्ष प्रकाश जाटव, राजेंद्र जादोरिया और शेरा बामने उनका सम्मान किया.

खाद, बीज व कीटनाशक विक्रेताओं का प्रदर्शन 27 को

इंदौर. इंदौर-उज्जैन संभाग के बीज एवं कीटनाशक तथा कृषि आदान विक्रेता 27 अप्रैल को आल इंडिया इनपुट डीलर एसोसिएशन एवं जागरूक कृषि आदान विक्रेता संघ इंदौर के आहवान पर अपना कारोबार बंद रखकर कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कलेक्टर, कमिश्नर को अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन भेंट करेंगे. प्रदेश के करीब 20 हजार और इंदौर-उज्जैन संभाग के करीब 5 हजार व्यापारी इस आन्दोलन में शामिल होंगे. संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री, इंदौर जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण दुबे, सचिव जितेन्द्र जैन एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय रघुवंशी ने बताया कि खाद, बीज एवं कीटनाशक व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार का कई बार ध्यानाकर्षण करने के बाद भी अब तक कोई ठोस निराकरण नहीं किया गया है. इसके विरोध में महाराष्ट्र राज्य संगठन ने 27 अप्रैल से बेमुद्दत बंद का आह्वान किया है, जिसके समर्थन में देश के सभी राज्यों के कृषि आदान विक्रेता पहले चरण में 27 अप्रैल को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे. संगठन के प्रदेशाध्यक्ष मानसिंह राजपूत ने बताया कि इन सभी मुद्दों पर विभिन्न संगठनों की ओर से लगातार संवाद किए जाने के बावजूद अब तक कोई समाधान नही निकल पाया है इसलिए अब 27 अप्रैल को इस एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के दौरान सभी व्यापारी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के नाम प्रत्येक तहसील, विकास खंड एवं जिला स्तर पर अपना कारोबार बंद रखकर जुलूस निकालकर ज्ञापन देंगे और यदि एक माह में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी खरीफ सीजन के पूर्व अनिश्चित कालीन हड़ताल जैसा कड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा.

छः स्वास्थ्य शिविरों में पहुंचे 6700 अग्रवाल बंधु

इंदौर. अग्रवाल समाज केन्द्रीय समिति, बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन एवं हेल्थ फॉर भारत फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में श्रीमती नीनादेवी अग्रवाल की पुण्य स्मृति में चलाए जा रहे स्वास्थ्य परीक्षण अभियान के अंतर्गत छठें स्वास्थ्य परीक्षण एवं निशुल्क जांच शिविर का आयोजन एयरपोर्ट रोड स्थित बाबाश्री रिसोर्ट पर सम्पन्न हुआ जिसमें दूसरे दिन 541 समाज बंधुओं ने शामिल होकर अपनी विभिन्न प्रकार की 32 जांचे कराई. इसके पूर्व पहले दिन 560 लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया. इस तरह कुल 1101 समाज बंधुओं ने इस शिविर में पहुंचकर मधुमेह एवं मोटापे से मुक्ति के अभियान का पहला चरण पार कर लिया. अब तक आयोजित हुए छः शिविरों में कुल मिलाकर 6701 लोगों ने अपनी प्रारम्भिक जांचे कराई है. अगला शिविर 25-26 अप्रैल को सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक गीता भवन प्रांगण में आयोजित होगा. शिविर के समापन अवसर पर हेल्थ फॉर इंडिया के 20 डॉक्टर्स की टीम का सम्मान भी किया गया. शिविर संयोजक किशोर गोयल, जगदीश बाबाश्री एवं नितिन अग्रवाल ने बताया कि अग्रवाल समाज केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद गोयल एवं बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन के प्रमुख विनोद अग्रवाल के मार्गदर्शन में अब तक शहर में विभिन्न स्थानों पर 5 बड़े शिविरों का आयोजन हो चुका है जिनमें करीब 5600 समाज बंधुओं ने अपनी जांचे कराई हैं। बाबाश्री रिसोर्ट पर आयोजित दो दिवसीय शिविर में 1101 लोगों ने लाभ उठाया। इस तरह अब तक 6701 लोग इन शिविरों से लाभान्वित हो चुके हैं.

राष्ट्रीय सीएसआर कॉनक्लेव का आयोजन कल

इंदौर. संस्था सत्या द्वारा आगामी 25 अप्रैल को राष्ट्रीय सीएसआर कांकलेव का आयोजन होटल सयाजी में करने जा रही है. इस आयोजन में देशभर के शिक्षाविद, कार्पोरेट्स, हेल्थ एक्सपर्ट और शोधार्थी छात्र शामिल होंगे. यह जानकारी संस्था सत्या की रंजना सहगल ने दी. उन्होंने बताया कि कांकलेव का विषय मानसिक स्वास्थ्य, जीवन शैली संबंधी विकार और निवारक आंकोलॉजी है. यह कानक्लेव एक ऐसे भविष्य की परिकल्पना करता है जहाँ स्वास्थ्य सेवा की जिम्मेदारी दान से परे जाकर मानव कल्याण में एक रण नीतक निवेश बन जाए, जिससे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को भारत के पारम्परिक स्वास्थय ज्ञान के साथ मिलाकर सभी के लिए स्थायी और निवारक स्वास्थ्य सेवा बन सके.

संतों की मौजूदगी में निकली जागरूकता रैली

इंदौर. भारतीय संस्कृति की आधार 'गौमाता' को सम्मान और संरक्षण दिलाने के लिए इंदौर के धर्मप्रेमियों और संतों ने निर्णायक संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है. गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत रणजीत हनुमान मंदिर से जन-जागरूकता वाहन रैली निकाली गई, जिसमें संतों की ओजस्वी उपस्थिति और गौ-भक्तों का भारी सैलाब उमड़ा. अभियान को नेतृत्व प्रदान कर रहे कृष्णायन गौशाला (हरिद्वार) के स्वामी अच्युतानंद महाराज, स्वामी गोपालाचार्य गोपालानंद सरस्वती और स्वामी रामगोपाल दास महाराज की गरिमामयी मौजूदगी में रैली का शुभारंभ हुआ. इस अवसर पर विश्वम के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी के साथ मनोज तिवारी, संजय कटारिया, अभिषेक उदेनिया एवं संगठन के समस्त पदाधिकारी प्रमुख रूप से शामिल हुए.

परोपकार जैन समाज की पहचान : रिजिजू

▸ जैन समुदाय के योगदान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित

इंदौर. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) ने मैरियट होटल में भारतीय अर्थव्यवस्था, शिक्षा और परोपकार में जैन समुदाय का योगदान विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया.

इस अवसर पर वीडियो संदेश के माध्यम से संगोष्ठी को संबोधित करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि परोपकार जैन समाज की पहचान है. अस्पताल, धर्मशालाएं, गौशालाएं और सामुदायिक रसोई सभी को गरिमा के साथ सेवा प्रदान करते हैं. जैन उद्यमी भारत की अर्थव्यवस्था को भी शक्ति देते हैं, रोजगार सृजित करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास में सहयोग करते हैं. समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन में योगदान दे रहा है. अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन मुख्य अतिथि के रूप में संगोष्ठी में शामिल हुए.

उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पीएम विकास योजना सहित विभिन्न सरकारी पहलों पर विस्तार से चर्चा की. कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संयुक्त सचिव डॉ. अत्य नंद द्वारा दिए गए औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ.

जैन मूल्य आज भी प्रासंगिक

एनसीएम की सदस्य एस. मुनव्वरी बेगम ने सेवा और उत्थान के प्रति जैन समुदाय की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि उनका योगदान भारत के सामाजिक ताने-बाने को लगातार मजबूत कर रहा है. एनसीएम के सदस्य बेरजिस देसाई ने कहा कि अहिंसा और बहुलवाद के जैन मूल्य आज की दुनिया में गहरे प्रासंगिक हैं. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सचिव अलका उपाध्याय ने स्वागत भाषण में कहा कि आयोग समुदाय की चिंताओं को दूर करने और हितों की रक्षा में सक्रिय रूप से लगा हुआ है. उद्घाटन सत्र को मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप; देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राकेश सिंघई; शांतिलाल मुथा फाउंडेशन के संस्थापक शांतिलाल मुथा और जैन इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गनाइजेशन के उपाध्यक्ष कमलेश सोजतिया ने भी संबोधित किया.

शिप्रा चौराहे पर जाम से हाल बेहाल, घंटों फंसे रहे लोग

इंदौर. उज्जैन मार्ग पर शिप्रा क्षेत्र में रोज लगने वाले जाम से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है. गुरुवार को भी शिप्रा चौराहे पर लंबा जाम लग गया, जिससे यात्री घंटों फंसे रहे. स्थानीय लोगों ने इसके लिए मांगलिया मेन रोड बंद होने और ट्रैफिक व्यवस्था को जिम्मेदार बताया है. शिप्रा चौराहे पर जाम की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. क्षेत्र के लोगों का कहना है कि मांगलिया रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रिज निर्माण के नाम पर मांगलिया व्यासखेड़ी रोड बंद कर दिया है, जिसके कारण सारा ट्रैफिक शिप्रा की ओर डायवर्ट हो रहा है. इससे रोजाना लंबा जाम लग रहा है और आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है. ऐसे हालात रोजाना बन रहे हैं, रोजाना की तरह गुरुवार को भी सांवेर और उज्जैन जाने वाले यात्री घंटों जाम में फंसे रहे. तीर्थ यात्रियों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों का आरोप है कि चौराहे के पास थाना होने के बावजूद ट्रैफिक नियंत्रण के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जाती, जिससे हालात बिगड़ जाते हैं.

टोल कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सड़क बंद करने का आरोप

किसान नेता हंसराज मंडलोई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जाम के कारण लोग उल्टी दिशा में वाहन चलाने लगते हैं, जिससे स्थिति और खराब हो जाती है और बायपास तक जाम की स्थिति बन जाती है. मंडलोई ने यह भी आरोप लगाया कि मांगलिया क्षेत्र में सड़क बंद करने का फैसला टोल कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए लिया है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्षेत्र के लोगों को इस जाम से कब मुक्ति मिलेगी. स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया तो वे शिप्रा में चक्का जाम करने को मजबूर होंगे.

संगीत की शाम में समाज सेवा का संगम

▸ स्टार बैंड टीम ने समाजसेवी मदन परमालिया को किया सम्मानित

इंदौर. शहर के स्टार बैंड द्वारा जाल सभागृह में आयोजित भव्य संगीत कार्यक्रम सारा ज़माना हसीनों का दीवाना धूमधाम से संपन्न हुआ. विजनरी ऑर्गनाइजर और प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक मनीषा यादव के नेतृत्व में आयोजित इस शाम ने न केवल संगीत प्रेमियों का दिल जीता, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को भी एक मंच पर लाया.

कार्यक्रम के दौरान समूह द्वारा समाजसेवी मदन परमालिया का विशेष सम्मान किया गया. उन्हें समाज के प्रति उनके निस्वार्थ योगदान और समर्पण के लिए स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया. बैंड की मुख्य कलाकार मनीषा यादव ने अपने सैक्सोफोन की धुनों से समां बांध दिया. उनके साथ द बैंड एनसेंबल के कलाकारों ने बेहतरीन जुगलबंदी पेश की. इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में इन्दु जैन मौजूद रहीं. साथ ही विशिष्ट अतिथियों में डॉ. मुक्ता रॉय संयुक्त सचिव, प्रदेश महिला कांग्रेस, चिन्तन बाकिवाला, उमेश सिंघानिया और विज़ी विंग्स के संस्थापक डॉ. अंशुल जैन व श्रेया अनसाने उपस्थित थे. कार्यक्रम की एंकर मिनी राजपाल ने मंच का संचालन करते हुए बताया कि स्टार बैंड टीम का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही नहीं, बल्कि समाज के नायकों को पहचान देना भी है. समाजसेवी मदन परमालिया के सम्मान ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा दिया. इस अवसर पर अशोक जैन, दीपक जाजोदिया, और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे. कार्यक्रम के अंत में मनीषा यादव ने सभी अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया.

गाय पालन दूध के लिए नहीं गोबर के लिए करें : गोपालाचार्य

▸ 27 अप्रैल को मनाया जाएगा गौ सम्मान दिवस

नवभारत न्यूज़

इंदौर. दिल्ली में संतों और गोसेवकों की एक महत्वपूर्ण बैठक में गौ सम्मान आह्वान अभियान की रूपरेखा तैयार की गई. इस अवसर पर अच्युतानंद महाराज (कृष्णायन गोशाला, हरिद्वार) और गोपालाचार्य गोपालानंद सरस्वती सहित कई संत और गोभक्त उपस्थित रहे.

उक्त जानकारी देते हुए इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में गोपालाचार्य गोपालानंद सरस्वती ने गाय पालन के विषय में कहा कि गाय दूध के लिए ना पाली जाए बल्कि गोबर के लिए पाली जाए जिससे जहरीली खेती जो यूरियां फर्टिलाइजर और अन्य के माध्यम से की जाती है वह गोबर की खाद स्तेमाल की जाए. वहीं देश की इकोनॉमी और आज के इस गैस संकट को देखते हुए गोबर के द्वारा गोबर गैस निर्माण कर देश के लिए ईंधन की भी जरूरत पूरी की जा सके जिससे देश की इकोनॉमी में सहायक हो सके. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यह अभियान किसी संस्था, संगठन या राजनीतिक दल के तहत नहीं चलेगा, बल्कि इसे पूरी तरह गौमाता और नंदी बाबा के सान्निध्य में संचालित किया जाएगा. अभियान का मुख्य उद्देश्य देश में गो संरक्षण और संवर्धन के लिए केंद्रीय कानून बनवाना, गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना और गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करवाना है.

गौ हत्या रोकने कड़े कानून बनाए जाएं

संतों ने सरकार से मांग की कि गौहत्या और गोतस्करी में शामिल लोगों के लिए कड़े कानून बनाए जाएं. साथ ही गोबर और गोमूत्र आधारित अनुसंधान विश्वविद्यालय, पंचगव्य औषधियों का नि:शुल्क वितरण, और गोशालाओं को मनरेगा से जोड़ने जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएं. अभियान के तहत जनवरी से मार्च 2026 तक देशभर में प्रचार-प्रसार किया गया. 27 अप्रैल को देश की सभी 5410 तहसीलों से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे जाएंगे, जिसमें करोड़ों हस्ताक्षर शामिल होंगे. यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो जुलाई और अक्टूबर 2026 में पुन: चरणबद्ध आंदोलन होगा. इसके बाद 2027 में दिल्ली में शांतिपूर्ण संकीर्तन और जनजागरण अभियान चलाया जाएगा. संतों ने स्पष्ट किया कि यह पूरा अभियान अहिंसक और गैर-राजनीतिक होगा, जिसमें केवल संकीर्तन, प्रार्थना और जनजागरण के माध्यम से संदेश दिया जाएगा.

एक नजर में ▸ **जीएसटी ट्रिब्यूनल की तैयारी के लिए मूट ट्रिब्यूनल का आयोजन**

अपील प्रक्रिया पर विशेषज्ञों ने दी महत्वपूर्ण जानकारी

इंदौर. मध्य प्रदेश टैक्स कंसलटेंट एसोसिएशन द्वारा जीएसटी ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल करने की प्रक्रिया एवं उसकी तैयारी को लेकर एक विशेष सेमिनार एवं मूट ट्रिब्यूनल का आयोजन किया गया. इस आयोजन का उद्देश्य कर सलाहकारों एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना रहा.

संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट सीए सुमित नीमा ने कहा कि जीएसटी कानून लागू होने के लगभग आठ वर्ष बाद ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई है. ऐसे में अब ट्रिब्यूनल के शुरू होते ही उस पर करीब चार लाख से अधिक अपीलों का भारी बोझ पड़ने की संभावना है. उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में कई कर प्रकरणों में अपील दाखिल नहीं हो सकी थी, जिससे देशभर में विवादित मामलों की संख्या काफी बढ़ गई है. उन्होंने सरकार से मांग की कि इतने बड़े बोझ को एक साथ ट्रिब्यूनल पर डालने के बजाय पुरानी अपीलों के समाधान के लिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम लागू की जाए, जिसमें 20 से 30 प्रतिशत राशि जमा कर मामलों का निपटारा किया जा सके. सेमिनार में सीए एस.एन. गोयल ने अपील की समय-सीमा पर जानकारी देते हुए बताया कि जिन मामलों में प्रथम अपील का आदेश 1 अप्रैल 2026 से पहले प्राप्त हो चुका है, उनकी अपील 30 जून 2026 तक दाखिल करनी होगी। वहीं, 1 अप्रैल 2026 के बाद प्राप्त आदेशों के खिलाफ अपील 3 माह के भीतर करनी अनिवार्य है. यदि अपील में देरी होती है, तो अधिकतम 3 माह तक की अतिरिक्त अवधि दी जा सकती है, जिसके लिए विलंब के उचित कारण बताते हुए आवेदन प्रस्तुत करना होगा. सीए कीर्ति जोशी ने जीएसटी अपील प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अपील फॉर्म जीएसटी एपीएल-05 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जीएसटीएटी पोर्टल पर दाखिल की जाती है. अपील के लिए विवादित कर राशि का 20 प्रतिशत पूर्व जमा करना अनिवार्य है. इसके साथ ही आदेश की प्रमाणित प्रति 7 दिनों के भीतर हार्ड कॉपी में जमा करनी होती है, अन्यथा अपील की तारीख मान्य नहीं होगी.

जीएसटी मामलों पर बहस कराई

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जीएसटी मूट ट्रिब्यूनल रहा. इसमें वास्तविक ट्रिब्यूनल के वातावरण में लंबित जीएसटी मामलों पर बहस कराई गई. लगभग 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एवं कर सलाहकारों ने 6 प्रमुख विवादित मुद्दों पर अपनी कानूनी क्षमता, शोध और मौखिक प्रस्तुति का प्रदर्शन किया. करदाता पक्ष की ओर से सीए उमेश गोयल, सीए नवीन खंडेलवाल, सीए अंकित करणपुरिया, सीए प्रखर गोयल एवं अंकुर अग्रवाल ने पैरवी की, जबकि विभाग की ओर से सीए शैलेन्द्र पोरवाल, सीए दिलीप राठौर एवं सीए अरविंद चावला ने अपना पक्ष रखा. इस दौरान वरिष्ठ सीए पी.डी. नागर एवं सीए आशीष गोयल ने न्यायाधीश की भूमिका निभाते हुए निर्णय सुनाए तथा प्रतिभागियों को ट्रिब्यूनल में पेश होने के दौरान ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी.

---

kotak | कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 27 बीकेसी, सी-27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051, (महाराष्ट्र)

शाखा कार्यालय : कोटक इन्फिनिटी, 5वीं मंजिल, ज़ोन IV, बिल्डिंग नंबर 21, इन्फिनिटी आईटी पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास, जनरल ए के वैद्य मार्ग, मलाड (पूर्व), मुंबई 400097

कॉर्पोरेट पहचान संख्या - L65110MH1985PLC038137, www.kotak.com

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) सहपठित सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) के तहत अचल संपत्ति के कब्जे के संबंध में नोटिस

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत और सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) और 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 09-05-2016 को एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें पक्षों- 1) आर्या फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में परिसमापन में), 2) श्री नानूराम अग्रवाल, 3) श्री सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, 4) श्रीमती सुरुचि अग्रवाल, 5) मेसर्स आर्या इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, 6) मेसर्स आर.एस. इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को रु. 7,79,35,527.81 (रु. सात करोड़ उन्यासी लाख पैंतीस हजार पांच सौ सत्ताइस और इक्यासी पैसे मात्र) की राशि, नोटिस में उल्लिखित संबंधित उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) से 31-03-2016 तक की बकाया राशि, साथ ही 01-04-2016 से भुगतान/वसूली (बकाया राशि) तक उस पर संविदात्मक दरों पर आगे के ब्याज और अन्य शुल्कों को उक्त मांग नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था. उक्त उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) द्वारा पूरी राशि चुकाने में विफल रहने पर, इसके द्वारा उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अप्रैल, 2026 के इस 21वें दिन को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है. विशेष रूप से उक्त उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) और आम जनता को एतद् द्वारा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के कंसोर्टियम लेंडर्स के प्रभार के अधीन होगा. उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है.

अचल संपत्ति का विवरण

मेसर्स आर्या फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले औद्योगिक प्लॉट नंबर 20 और 22-बी, औद्योगिक क्षेत्र 1, पीथमपुर, धार में स्थित औद्योगिक संपत्ति का ईएम (EM), जिसका क्षेत्रफल 15990 वर्ग मीटर है, जिसमें सभी मौजूदा भवन, उस पर स्थित संरचनाएं और भवन और संरचनाएं शामिल हैं, जो संबंधित बंधक की तारीख से/उसके बाद कभी भी वहां बनाए/निर्मित किए जा सकते हैं और उसमें होने वाले सभी अतिरिक्त निर्माण और पृथ्वी से जुड़े या पृथ्वी से स्थायी रूप से जुड़े सभी फिक्स्चर और फर्नीचर और प्लांट और मशीनरी, वर्तमान और भविष्य दोनों शामिल हैं.

हस्ताक्षर/-
प्रणय भरुचा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अधिकृत अधिकारी
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

दिनांक : 24.04.2026
स्थान : पीथमपुर, धार, मध्य प्रदेश